

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2413/2012/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी

सिरोही

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स श्रीराज एजेन्सीज

सिरोही

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

श्री पी.एम.चौपडा

अभिभाषक

निर्णय दिनांक 21.09.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 07/आरवैट/सिरोही/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2008-09 में इनपुट क्लेम किया परन्तु खरीद राशि में से डिस्काउण्ट एवं रिबेट ऑन परचेज कम करके शेष राशि को ही व्यापार खाते/अंकेक्षण प्रतिवेदन में खरीद राशि के रूप में दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रकार दर्शायी गयी खरीद अनुपात में इनपुट राशि को रिवर्स करते हुए ब्याज आरोपित किया तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति भी आरोपित की, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आगत कर पर आरोपित ब्याज को अपास्त करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रख कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2012 से क्षुब्ध होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2008-09 में इनपुट क्लेम किया परन्तु खरीद राशि में से डिस्काउण्ट एवं रिबेट ऑन परचेज (discount and rebate on purchase) कम करके शेष राशि को ही व्यापार खाते/अंकेक्षण प्रतिवेदन में खरीद राशि के रूप में दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रकार दर्शायी गयी खरीद अनुपात में इनपुट राशि को रिवर्स करते हुए ब्याज आरोपित किया, जो पूर्णतः विधिक

है, किन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित ब्याज को अपास्त किया गया है, जो अनुचित होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 06.10.2010 को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सीमेन्ट कम्पनी से वेट इनवाइसेज के आधार पर माल खरीद कर डीलर के रूप में विक्रय किया है तथा व्यवहारी ने अपने बिक्री में से किसी प्रकार का किसी व्यवसायी को दिया गया टर्नओवर कमीशन इत्यादि अदा कर बाद नहीं लिया है चूंकि व्यवहारी ने समस्त माल कम्पनी से कय किया है तथा कम्पनी एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष के अन्त में टर्नओवर के आधार पर कम्पनी डिस्काउण्ट/टर्नओवर कमीशन देती है जिससे व्यवहारी ने अपने कुल खरीद मूल्य में कम किया है जबकि वैट इनवाइस के आधार पर जो उसका खरीद मूल्य बनता है उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर चुकाया है, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने का व्यवहारी हकदार है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार का विशिष्ट नोटिस दिये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 2(36) एक्स-2 के प्रावधान उस विक्रेता जो टर्न ओवर डिस्काउण्ट देता है, पर लागू होते हैं न कि क्रेता पर, प्रत्यर्थी व्यवहारियों ने पूरा कर विक्रेता को चुका दिया तथा विक्रेता कंपनी ने यह सम्पूर्ण वेट राशि राज कोष में जमा करवायी। चूंकि धारा 2(36) का प्रावधान प्रत्यर्थियों पर लागू नहीं होता अतः टर्न ओवर डिस्काउण्ट पर इनपुट टैक्स को रिवर्स करना अविधिक तथा नियम विरुद्ध है। प्रत्यर्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम अभिवाक् किया कि इनपुट क्रेडिट रिवर्स करने के प्रावधान धारा 18 की उप धारा (3) (I to V) में वर्णित है चूंकि अपीलार्थी व्यवसायी का मामला धारा 3 की उप धारा (I to V) से आच्छादित नहीं होता है अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश कानून की परिधि से बाहर है। इस संबंध में केरला उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. प्रिया एजेन्सीज् आदेश दिनांक 02.04.2008 में यह निर्धारित किया है कि टर्न ओवर डिस्काउंट के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। धारा 18(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीद वेट इनवाइस के अनुसार इनपुट क्रेडिट ली जायेगी, प्रत्यर्थियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट वेट इनवाइस एवं वेट-07 विवरण पत्रों के अनुसार क्लेम की गई है। व्यवसाई द्वारा वेट-07 तिमाही विवरण पत्रों के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं जो नियमानुसार हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त आदेश में इनपुट टैक्स रिवर्स कर एवं उस पर ब्याज आरोपित किया है वह अविधिक है। वर्ष के अंत में एडजस्टमेंट के लिये किसी भी जमाखर्च को करना कय या विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है और वह



क्रय व विक्रय को वेट एक्ट के फार्म-07 एवम् फार्म-08 को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी क्रय मूल्य पर इनपुट टैक्स लेने के लिये पात्र है। कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने तरीके से भुगतान किये गये वेट को रिवर्स किया है वह अविधिक है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सीमेन्ट निर्माता कम्पनी से वेट इनवाइस के आधार पर सीमेन्ट खरीद कर उसका विक्रय ग्राहकों को किया है। सीमेन्ट निर्माता कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद सीमेन्ट की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अपने वितरक (Distributors) प्रत्यर्थी को वर्ष के दौरान उनके द्वारा क्रय की गई सीमेन्ट के टर्न ओवर के आधार पर वर्ष के अन्त में डिस्काउंट/इन्सेन्टिव प्रदान किया गया है। इस प्रकार सीमेन्ट कम्पनी द्वारा वर्ष के अन्त में डिस्काउंट/इन्सेन्टिव की राशि के क्रेडिट नोट संबंधित वितरक के पक्ष में जारी किये गये जिनका इन्द्राज प्रत्यर्थी ने अपने खाते में कर, कुल खरीद राशि में से डिस्काउन्ट/इन्सेन्टिव की राशि को कम कर ट्रेडिंग एकाउन्ट में शुद्ध खरीद राशि दर्शायी गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण द्वितीय के आधार पर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा एक्स पोस्ट फेक्टो (Ex Post Facto) दिये गये, इस डिस्काउन्ट/इन्सेन्टिव को अस्वीकार कर इस डिस्काउन्ट/इन्सेन्टिव के बराबर की राशि की खरीद कम मानते हुये प्रत्यर्थी द्वारा इस खरीद राशि पर लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अस्वीकार करते हुये रिवर्स टैक्स एवम् ब्याज आरोपित किया गया।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के विवेचन के पश्चात् वेट अधिनियम के सुसंगत प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है :-

Section 2(17) "Input tax" means tax paid or payable by registered dealer in course of business, on the purchase of in goods made from a registered dealer.

Section 2(33) "Revers tax" means a part of the input tax for which credit as been availed in contravention of the provisions of section 18.

Section 2(36) "Sales price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less in a sum allowed by way of any kind of discount or rebett according to the practicee normally prevailing in the trade, but including of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or sevicees rendered at the time of before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act,



Explanation 1 :-

Explanation 2:- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded.

Section 18. Input Tax Credit.- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

"(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-



(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

(4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

उपर्युक्त परिभाषित "इनपुट टैक्स" से आशय उस कर राशि से है जो पंजीकृत क्रेता व्यवसाई द्वारा खरीद के दौरान कर के रूप में भुगतान की गई है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवसाई द्वारा वक्त क्रय वेट इन्वॉइसेज के आधार पर जो राशि कर के रूप में विक्रेता को भुगतान की गई है उस पर ही आगत कर का मुजरा क्लेम किया गया है।

विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉइसेज में वसूल किये गये कर की राशि का भुगतान क्रेता प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया जाकर वेट-07 के तहत इस खरीद पर भुगतान किये गये कर की राशि का आई.टी.सी क्लेम पेश किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में धारा 18(2) के प्रावधानों के अनुसार वेट राशि का आई.टी.सी. का क्लेम प्रत्यर्थी व्यवसाई द्वारा समयावधि में पेश किया गया है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार "रिवर्स टैक्स" से आशय इनपुट टैक्स की उस राशि से है जिसका क्रेडिट धारा 18 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये लिया गया हो।

यह भी स्पष्ट है कि वेट अधिनियम की धारा 18(1) क्लॉज ए से जी तक के किसी प्रावधान का इन हस्तगत प्रकरण में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तथा 18(2) के प्रावधान की पालना की गई है। धारा 18(3) में अंकित जिन स्थितियों में आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है, वो कोई स्थिति इस प्रकरण में घटित नहीं हुई। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में धारा 18 के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिस आधार पर रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया वो आधार विधिसम्मत नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में विक्रय मूल्य को परिभाषित किया है। इस उप धारा के स्पष्टीकरण द्वितीय में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री करते समय विक्रय पर्वों में अंकित केश या ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का हिस्सा नहीं

होगी परन्तु भूतलक्षी प्रभाव से (Ex post Facto) दिये गये डिस्काउंट या इन्सेटिव की राशि का विक्रय मूल्य से कम (Exclude) नहीं किया जायेगा। यानि भूतलक्षी प्रभाव से दिये जाने वाले डिस्काउंट/रिबेट से विक्रय मूल्य की राशि अप्रभावित रहेगी।

हस्तगत प्रकरण में माल की बिक्री होने के बाद विक्रेता द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से डिस्काउंट/इन्सेटिव क्रेता के पक्ष में जारी किये गये। अतः उपर्युक्त स्पष्टीकरण द्वितीय के प्रभाव स्वरूप विक्रेता द्वारा दिये गये भूतलक्षी डिस्काउंट की राशि उसके विक्रय मूल्य में से कम नहीं की जायेगी और न ही बिक्री पर आउटपुट टैक्स (Output Tax) की देयता में कमी की जावेगी।

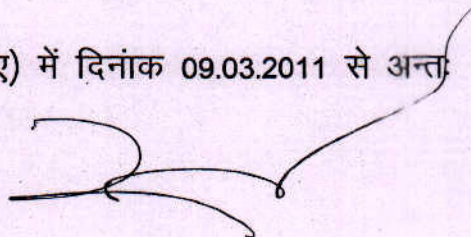
इस सन्दर्भ में प्रिया बनाम सी.टी.ओ. (2008) 14 वी.एस.टी. 493 के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रासंगिक है। इस निर्णय के सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

“While paying tax on sales turnover, the petitioners have taken input tax credit on tax collected by supplier. The suppliers, periodically, give credit not to the petitioners by way of incentives for sale of various goods under various schemes. The assessing officer in all the case considered the amount covered by the credit notes as discount given by the suppliers consequently, while giving input tax credit, tax attributable to the credit note amount was reduced, thereby reducing the input tax credit on credit not amounts were reduced because petitioner have not complied by b circular. As per circular the recipients of credit notes should produce certificate from the suppliers to the effects that the suppliers have not claimed deduction of the credit note amount toward discount of otherwise in their turnover and tax is paid on the full amount shown in the bills.

Petitioner challenged the validity of the circular. Kerala High court held that circular is beneficial to the petitioner, as if the suppliers have not claimed deduction of credit note amount as discount and paid full tax shown in the sale bill, then petitioner are entitled to full input tax credit based on purchase bills, provided the cement supplying companies issue deductions to the petitioner and their distributors to the effect that entire tax shown in their bills to the buyers are paid and no deduction in the turnover is claimed by them towards trade discount based on credit notes.”

राजस्थान राज्य में केरल राज्य के समान इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में विक्रेता व्यवसायी द्वारा का देयता कम न करने के प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है।

वेट अधिनियम की धारा 18 में उप धारा 3 (ए) में दिनांक 09.03.2011 से अन्तः स्थापित की गई जो इस प्रकार है :-



(3-A)" Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods"

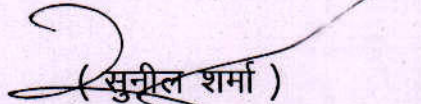
उपर्युक्त उपधारा को अन्तः स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के निम्नांकित उद्देश्य व कारण बताये गये हैं :-

In certain trades goods are being sold and tax on such sales is being recovered from the purchaser, but at later stage seller provides incentive to the purchasing dealer in the form of credit notes or subsidy etc. Such purchasing dealers after selling goods at subsidized rates claim refund of tax paid at earlier stage. In order to check this tendency a new sub-section (3A) is proposed to be inserted in section 18 of the Rajasthan Value Added Tax 2003.

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम के गलत व्याख्या की जाकर बिना उचित आधार के आई.टी.सी का क्लेम अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किया गया जबकि हस्तगत प्रकरण में धारा 18 के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिये रिवर्स टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निष्पादित की गई कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विस्तृत विवेचन के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नजर नहीं आती है।

फलस्वरूप प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य